ई-संदेश

28 अगस्त, 2025 | अंक 168

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश की अंतरिक्ष तक उड़ान

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) सकुशल वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के सपूत, अंतरिक्ष यात्री एवं ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी के लखनऊ आगमन पर नागरिक अभिनंदन

- सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत तथा कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणाम प्रदेश के विकास के रूप में दिखाई दे रहे : मुख्यमंत्री
- प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए: मुख्यमंत्री
- भारत के संविधान की मूल थीम न्याय, समता और बंधुता पर आधारित : मुख्यमंत्री
- टीम वर्क से सार्थक परिणाम आते हैं: मुख्यमंत्री
- राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन अर्जित करने वाले छात्रों के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति जारी करेगी: मुख्यमंत्री
- उ0प्र0 के युवा अपार ऊर्जा के स्रोत, इनकी प्रतिभा व सामर्थ्य की मांग देश और दुनिया में हो रही : मुख्यमंत्री
- इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र: मुख्यमंत्री
- युवाओं को सही दिशा प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत तथा कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणाम प्रदेश के विकास के रूप में दिखाई दे रहे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अगस्त, 2025 जनपद एटा में श्री सीमेण्ट प्लाण्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत तथा कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणाम हम सभी को प्रदेश के विकास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यही विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत आज एटा को श्री सीमेन्ट के रूप में नया उपहार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद एटा आज विकास की बुलन्दियों को छू रहा है। यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर लेन कनेक्टिविटी तथा अनेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब एटा को बेहतरीन कानून-व्यवस्था व विकास के लिए जाना जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एटा के जवाहरपुर में सरकार द्वारा थर्मल पावर प्लाण्ट स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से लगभग डेढ़ हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन होता है। लोगों को स्वच्छ और सुन्दर वातावरण प्रदान करने तथा प्लाण्ट के फ्लाईएश के बेहतरीन उपयोग के लिए श्री सीमेन्ट परिवार ने लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की लागत से यह श्री सीमेन्ट प्लाण्ट स्थापित किया है। थर्मल पावर प्लाण्ट तथा श्री सीमेन्ट प्लाण्ट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन के माध्यम बन रहे हैं। श्री सीमेन्ट प्लाण्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 03 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को निरन्तर प्राप्त होने वाले अन्य निवेश प्रस्तावों के माध्यम से भी नौकरी व रोजगार की नई सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यह केवल एक प्लाण्ट का उद्घाटन नहीं, श्री सीमेन्ट प्रदेश सरकार का पुराना सहयोगी है, जिसने प्रदेश में निवेश करने के लिए हमेशा उत्सुकता दिखाई है। बांगर परिवार ने चित्रकूट में पावर रिन्यूल एनर्जी का 40 मेगावाट का प्लाण्ट स्थापित किया है। हमने प्लाण्ट के लिए उन्हें ओपन एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई है। वह वहां पावर जनरेट कर, यहां खर्च कर सकते हैं। उनके द्वारा जो ग्रीन व सोलर एनर्जी वहां बनाई जा रही है, उसका उपयोग करने की सुविधा उन्हें इस प्लाण्ट में उपलब्ध कराई जा रही है। यह प्रदेश सरकार की नीति का परिणाम है कि सरकार ने उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा के साथ जोड़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में अब तक 70 हजार युवाओं को ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही, उन्हें मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। इसके माध्यम से युवा नए उद्यम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वयं को देश की विकास यात्रा से अलग नहीं कर सकता है। यहां देश का प्रत्येक छठा व्यक्ति निवास करता है। विगत साढ़े आठ वर्षों में विकास के माध्यम से प्रदेश को नई पहचान प्राप्त हुई। वर्ष 2017 के पहले जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, आज वही प्रदेश 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल हुआ है। सेक्टोरियल पॉलिसीज व शुद्ध नीयत के माध्यम से अब तक 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यदि एक श्री सीमेन्ट प्लाण्ट 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार दे सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख युवा नौकरी और रोजगार न पा सकते हों।पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 7वें नम्बर पर थी। विगत 08 वर्षों में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश अब देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण से निवेशकों के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरुप प्रदेश को बड़ी मात्रा में निवेश की प्राप्ति हुई।

प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 अगस्त, 2025 को यहां लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए और वित्तीय संसाधनों का आवंटन नगर निकायों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केन्द्रित स्वरुप में विकसित करना है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरुम व आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ई0 वी0 चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' आधारित ढाँचे भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। उदाहरणस्वरुप, लखनऊ और गोरखपुर स्थित एकीकृत कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे नगर पालिकाओं को सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता मिलेगी तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग सम्भव होगा।

बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करते हुए इसके लिए आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर शीघ्र तैयार किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने सभी नगर निगमों में निवासियों के विविध कर बकाये में विसंगतियों के तत्काल समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में अभियान चलाकर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का यथोचित व संतुष्टिपरक समाधान कराया जाए। सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए।

बैठक में नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि विगत लगभग 20 वर्षों से इन सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरुप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति तथा नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज एवं बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पी0पी0पी0 मोड पर प्राथमिकता के साथ प्रारम्भ किया जाए, जिससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हों।

भारत के संविधान की मूल थीम न्याय, समता और बंधुता पर आधारित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 अगस्त, 2025 को यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के संविधान की मूल थीम न्याय, समता और बंधुता पर आधारित है। किसी भी राज्य के परसेप्शन को जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया के किसी भी राज्य से जुड़ा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रदेश में स्थित है। 102 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यह केवल संघ का अधिवेशन मात्र नहीं, बल्कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर जोर देने का प्रयास है, जो किसी संस्था के भविष्य को तय करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि हमें सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो न्याय को सुगम और त्वरित बनाना पड़ेगा। गत एक वर्ष में प्रदेश के जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 01 करोड़ 15 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं। लम्बित मामलों के निस्तारण का परिणाम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मामलों के निस्तारण में हमारी गति जितनी अधिक होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे। प्रदेश सरकार न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़, न्याय को सुगम व त्वरित बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में 01 जुलाई, 2024 से तीन नए कानून लागू किए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों ने तत्परता के साथ इन्हें लागू किया। तीनों नए कानून न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध पर राज्य सरकार अत्यन्त गम्भीर है। विभिन्न पॉक्सो न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा अन्य न्यायालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब तक 381 न्यायालयों का गठन कराया जा चुका है। केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत कोर्टरूम एवं आवास निर्माण परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 148 करोड़ रुपये से अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 239 करोड़ रुपये से अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 75 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदीय न्यायालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फायर फाइटिंग उपकरण आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों हेतु अब तक 19 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। जैसाकि यहां न्यायिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। ऐसा करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपये से अधिक की धनराशि को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश के न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में न्यायिक अधिकारियों के 400 बेडेड हॉस्टल निर्माण हेतु 54 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। यह परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्तिगण के लिए प्रयागराज में आवास निर्माण हेतु 62 करोड़ 41 लाख रुपये तथा लखनऊ बेंच के न्यायमूर्तिगण की आवासीय सुविधा हेतु 117 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 99 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से एक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स

कॉम्प्लेक्स निर्मित किया जा चुका है। संस्थान में अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कम्प्यूटर लैब के रखरखाव के लिए 08 करोड़ 77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। संस्थान के ऑडिटोरियम को 02 करोड़ 36 लाख रुपये से अधिक की लागत से उन्नत किया गया है। संस्थान परिसर पर 01 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक की धनराशि से अधिकारी आवासों में वृहद मरम्मत कार्य कराए गए हैं। संस्थान में अन्य आनुषंगिक रखरखाव के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक कुल 81 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नवीन कार्यालय भवन 22 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक की धनराशि से निर्मित किया गया है। डॉ0 राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु 387 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 110 ग्राम न्यायालय क्रियाशील किए जा चुके हैं। अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में न्यायालयों में उन्नत तकनीक, वाद प्रबंधन, डेटाबेस विश्लेषण तथा ए0आई0 का उपयोग कर न्यायिक व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत है। वैकल्पिक विवाद अनुतोष व समाधान तंत्र को भी और भी सुदृढ़ किया जाएगा। न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के साथ-साथ इण्टर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अन्तर्गत ई-कोर्ट्स, ई-पुलिसिंग, ई-प्रिजन, ई-प्रॉसीक्यूशन तथा ई-फॉरेंसिक के एकीकरण से प्रदेश की न्याय व्यवस्था को उन्नत और उत्कृष्ट बनाने के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रदान करने तथा मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की विषम परिस्थितियों में उन्हें तथा उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए न्यायिक अधिकारी कल्याण कोष की स्थापना की गयी है। वर्ष 2018 में प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपये के कॉरपस फण्ड की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपये का कॉरपस फण्ड उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को उपलब्ध कराने की घोषणा करती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में 01 करोड़ 15 लाख से अधिक मामले लम्बित हैं। जिससे जनपदीय न्यायालय कक्षों में वादकारियों की भीड़ लगी रहती है और प्रतिकूल मौसम में क्षमता के अनुरुप कार्य करना दुरुह हो जाता है। न्याय विभाग द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय कक्षों, कार्यालय कक्ष तथा न्यायिक अधिकारीगण के कक्ष में एयरकण्डीशनर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी सेवा संघ द्वारा जनपदीय न्यायालयों में डेपोजिशन राइटर (साक्ष्य लेखक) के पदों की मांग की गयी थी। जनपदीय न्यायालयों में प्रत्येक न्यायालय के लिए डेपोज़िशन राइटर की आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है। ताकि न्यायिक कार्यों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामला सामने आया है। प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव प्राप्त कर प्रत्येक जनपद में इस कार्य को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी।इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ की स्मारिका का विमोचन किया।

टीम वर्क से सार्थक परिणाम आते हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी 23 अगस्त, 2025 को मानबेला, गोरखपुर में 02 कल्याण मण्डपम् का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब टीम वर्क से प्रयास होता है, तभी परिणाम आते हैं। आज गोरखपुर और प्रदेश का विकास इसी सार्थक प्रयास का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि विकास की इस प्रक्रिया में हम नकारात्मकता को त्याग कर, एक सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाने तथा विकसित भारत की सुदृढ़ नींव के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक साथ दो कल्याण मण्डपम् गोरखपुरवासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। इनमें बाबा गम्भीरनाथ नगर, मानबेला में और राप्तीनगर विस्तार के पीरू शहीद में शादी-विवाह, मांगलिक कार्यों, सभा आदि सहित अन्य सार्वजनिक कार्यों के आयोजन के लिए कल्याण मण्डपम् शामिल है। प्रदेश के अन्य नगरों में भी ऐसे कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप तथा स्पोर्ट्स सिटी आवासीय योजना के आवंटियों को आवंटन पत्र वितरित किए। उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन तथा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुरवासियों को कल्याण मण्डपम् के लिए बधाई देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में उनकी विधायक निधि से 01 करोड़ 86 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इनके लिए भूमि की व्यवस्था करते हुए शेष धनराशि लगायी। आज यह भव्य कल्याण मण्डपम् बनकर लोकार्पित हुए हैं। कल्याण मण्डपम में 11 से 25 हजार रुपये देकर लोग अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे, जिनके लिए बड़े होटलों में 05 से 10 लाख रुपये देने पड़ते। गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा गोरखपुर नगर निगम द्वारा 05 ऐसे कल्याण मण्डपम् बनाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल्याण मण्डपम् में दिव्यांगजन के लिए रैम्प बनाए गए हैं। सभागार में 300 लोग एक साथ बैठकर मांगलिक कार्यक्रम का आनन्द ले सकते हैं। ऊपर मंडप बनाया गया है। भोजन के लिए रसोई बनाई गई है। टॉयलेट दिए गए हैं। यहां एक बड़ा लॉन भी उपलब्ध कराया गया है। पार्किंग की व्यवस्था भी है। इनकी लागत ढाई करोड़ रुपये है। विकास निधि के पैसे का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है, यह मण्डपम् इसका उदाहरण है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां पर स्पोर्ट सिटी भी बन रही है। यहां का कोई भी नौजवान खेलकूद के कार्यक्रमों से जुड़ना चाहता है, तो उसे एक मंच मिल गया है। राजेन्द्र नगर पश्चिम में भी बाबा राघवदास के नाम पर हमने जी0डी0ए0 के साथ मिलकर विधायक निधि से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। 200 नौजवानों ने वहां रजिस्ट्रेशन कराया है, जो खेल-कूद के विभिन्न कार्यक्रमों से वहां जुडे हैं। वहां बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग रेंज, क्रिकेट, हॉकी सहित अन्य गतिविधियां चल रही हैं। इसमें इन्डोर और आउटडोर गेम की सुविधा है। इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स यहां राप्तीनगर में बन रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें अपने स्तर पर, अपने वॉर्ड, अपने जनपद, अपने नगर, अपने क्षेत्र, अपनी-अपनी फील्ड में पारंगत होकर आगे बढ़ने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में वर्ष 2047 का उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 24-25 घण्टे तक बहस चली। वर्ष 2047 का मतलब एक विकसित गोरखपुर। वर्ष 2047 का मतलब यहां के हर नागरिक के पास उसके हाथ को काम हो, उसके चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के पास बेहतरीन अवसर हो, उच्च शिक्षा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई दें। इस प्रकार की स्थिति अपने शहर में भी पैदा करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन अर्जित करने वाले छात्रों के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति जारी करेगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी 25 अगस्त, 2025 को यहां लोकभवन में ऐतिहासिक एक्सिओम-4 मिशन के सफलतापूर्वक संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई0एस0एस0) से कुशल वापसी के बाद अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को लखनऊ आगमन पर आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनन्दन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के किसी नागरिक को 04 दशक बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्में और यहीं पर अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राप्त हुआ। उनकी सफलतम यात्रा के उपरान्त आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका पहली बार आगमन हुआ है। उनका आगमन हम सभी को आह्लादित करता है। श्री शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, जो किसी स्पेस मिशन के साथ जुड़े हैं। राज्य सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च अध्ययन अर्जित करने वाले छात्रों के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक छात्रवृत्ति जारी करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा हम सभी के लिए कौतूहल का विषय थी। हर भारतवासी उनकी यात्रा को बड़े विश्वास व आशा भरी निगाहों से देख रहा था। उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री, भारत माता के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ के लाल हैं। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त की है। अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल वापसी के उपरान्त आज उनका अपने घर लखनऊ में आगमन हुआ है। आज इस मंच के माध्यम से उनके अनुभवों का लाभ भी हमें प्राप्त हुआ है। श्री शुभांशु शुक्ला के पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन में ही अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पर ध्यान दिया। माता-पिता के संस्कारों से पुत्र ने आगे बढ़कर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आज उनकी उपलब्धि का लाभ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले स्पेस का क्षेत्र हमारे लिए अछूता सा था। हमने इस क्षेत्र का बहुत उपयोग नहीं किया। वर्तमान में हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। कहीं पर सूखा है, तो कहीं पर अतिवृष्टि की स्थिति है। फसल चक्र पर इसका असर पड़ा है। आकाशीय बिजली तथा बाढ़ के दौरान जन-धन की हानि होती है। आपदा प्रबन्धन तथा स्वास्थ्य सेक्टर सहित अन्य अनेक चुनौतियां हैं। यदि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का बेहतरीन उपयोग किया जा सके, तो हम न केवल आपदा को कम करने में सफल हो सकते हैं, बल्कि अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम नागरिकों को ईज़ ऑफ लिविंग तथा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सफल हो सकते हैं, बाढ़ और सूखे के बेहतर प्रबन्धन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव इस दिशा में हमारे पास हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्टेम एजुकेशन की बात कही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो युवा कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अवसर हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी इन युवाओं के लिए विकास के नए द्वार खोल सकती है। आने वाली चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में भारत विगत 11 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। आज का यह नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के बाद लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में आगमन के अभिनन्दन का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि भविष्य की उपलब्धियों के नए द्वार खोलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से यह अपेक्षा की कि विभाग प्रदेश में जो कार्यक्रम संचालित कर रहा है, उन सभी में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ ले। आज से 3-4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में कोई पाठ्यक्रम नहीं संचालित होते थे। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा ए0के0टी0यू0 सहित प्रदेश के एक दर्जन से अधिक संस्थानों ने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिग्री कोर्स प्रारम्भ किए हैं। यह दर्शाता है कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश के यह संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं।

उ0प्र0 के युवा अपार ऊर्जा के स्रोत, इनकी प्रतिभा व सामर्थ्य की मांग देश और दुनिया में हो रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 अगस्त, 2025 को यहां लखनऊ में तीन दिवसीय रोजगार महाकुम्भ-2025 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मिशन सोसाइटी के 'लोगो' का लोकार्पण, श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट, ई-कोर्ट पोर्टल एवं अटल आवासीय विद्यालयों में इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का शुभारम्भ किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा अपार ऊर्जा के स्रोत हैं। युवाओं ने अपनी प्रतिभा व सामर्थ्य से औद्योगिक क्षेत्र को लाभान्वित किया है। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा व सामर्थ्य की मांग देश और दुनिया में हो रही है। रोजगार महाकुम्भ-2025 के अवसर पर यहां इण्डस्ट्री और इम्प्लॉयर एक साथ जुड़ रहे हैं। एक ओर संस्थाएं रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं, तो दूसरी ओर स्किल डेवलपमेण्ट के साथ जुड़कर युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। विकसित भारत की संकल्पना में प्रत्येक व्यक्ति व संस्था अपना योगदान दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लागू करने वाले, देश के अग्रणी राज्यों में है। यू0पी0 स्टार्टअप मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में बेहतरीन कार्य किये जा रहे हैं। आज प्रदेश के युवाओं की मांग दुनिया के अनेक देशों में हो रही है। पहले प्रदेश के युवाओं को अन्य देशों में जाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें सम्बन्धित देशों की भाषा से सम्बन्धित समस्या होती थी। अब प्रदेश सरकार युवाओं को अन्य देशों की भाषाओं में पारंगत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्हें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी आदि भाषाओं की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत 08 वर्षों में संचालित योजनाओं के परिणामस्वरूप यहां के युवा स्वयं अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की पंजीकृत इकाइयों को 05 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया गया है। इन इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'वोकल फॉर लोकल' का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की आधारशिला बन रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की श्रृंखला में प्रदेश में परम्परागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ सस्ता, सुलभ व सुगम ऋण तथा टूलकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में परम्परागत हस्तशिल्पियों को सम्मान मिल रहा है। उन्हें रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आज यहां कुछ पोर्टल लॉन्च किये गये हैं। श्रम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारम्भ हुआ है। इस पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय तथा श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की व्यवस्था की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की गयी है। श्रम अधिकारों से जुड़ी सेवाओं को 24 घण्टे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक निगम का गठन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्य करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारण्टी प्रदान की जाएगी। नियोक्ता एवं नियुक्ति पाने वाले को श्रम एवं सेवायोजन पोर्टल से जुड़ना होगा। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वह कार्मिक को निर्धारित वेतन समय पर उपलब्ध कराए। किसी कार्मिक के वेतन में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिभाशाली युवाओं को शोषण से बचाने के लिए इस बेहतरीन व्यवस्था को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारण्टी तथा आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 अगस्त, 2025 को लखनऊ में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025' के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह नीति आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेण्टर बनाने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025' लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। अपार सम्भावनाओं वाले इस सेक्टर का लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश ने औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है। अब समय है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इण्डिया' के संकल्प को मजबूती देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।

मुख्यमंत्री जी को विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2014-15 में देश में जहाँ मात्र 1.9 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनते थे, वहीं वर्ष 2024-25 में यह आँकड़ा 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। मोबाइल उत्पादन 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात किये गये।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। निवेशकों को एकल विण्डो प्रणाली के माध्यम से सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए तथा कौशल विकास कार्यक्रम उसी के अनुरूप संचालित हों।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। यह नीति न केवल विदेशी निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगी।

युवाओं को सही दिशा प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 अगस्त, 2025 को लखनऊ में मिशन रोजगार के अन्तर्गत चयनित 2,425 मुख्य सेविकाओं तथा 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक प्रतिभाशाली व ऊर्जावान युवा हर सम्भव प्रयास करता है। वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। युवाओं के सपनों को मंच प्रदान करने का दायित्व प्रत्येक लोकप्रिय सरकार का होता है। युवाओं को सही दिशा प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आज 2,438 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुपोषित माताओं और नवजात शिशुओं के लिए चल रहे पोषण अभियान की मॉनीटरिंग के लिए 2,425 मुख्य सेविकाएं तथा 13 फार्मासिस्ट सम्मिलित हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनमें प्रदेश के सुदूर जनपदों में रहने वाली बेटियों तथा जनपद लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच रहने वाली थारु जनजाति की बेटियों का सफल होना चयन की निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की बेटियां चयनित होकर शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रही हैं।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की बेटियां चयनित होकर शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रही हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कार्मिकों की भर्ती की गई। इसमें 12,045 बेटियां सम्मिलित हैं। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश पुलिस बल में केवल 10 हजार महिला पुलिस कार्मिक थीं। विगत 08 वर्षों में 40 हजार से अधिक महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 01 लाख 56 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसमें ज्यादातर बेटियां सम्मिलित हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न करायी गयी है। साथ ही 03 हजार से अधिक आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रूप में प्रोन्नत कर उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी है। 22,290 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रदेश के बचपन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि बचपन स्वस्थ है, तो आगे का जीवन समृद्ध के पथ पर अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री जी ने नवचयनित अभ्यर्थियों से कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करना चाहिए। यदि आप पूरी प्रतिबद्धता व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गारन्टी देनी चाहिए कि वह न तो भेदभाव करेगा न ही किसी के साथ भेदभाव होने देगा। चयन प्रक्रिया में आपसे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आपको भी कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 में एक ऐसे भारत का लक्ष्य देशवासियों को दिया है, जो विकसित, आत्मनिर्भर तथा समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता आंगनबाड़ी केन्द्र तथा गांव की गलियों से होकर जाता है। नवजात शिशुओं व कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ बेहतरीन प्रयास करना होगा। सभी नव चयनित मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को शासन की मंशानुरुप स्वस्थ, सशक्त एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने तथा वर्ष 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का सम्यक् निर्वहन करना होगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित